

यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा ग्राहकों से शुल्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफवाहों को किया खारिज

एमडीआर केवल व्यापारियों से जुड़ा आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

नई दिल्ली, 07 अगस्त यूपीआई से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने कहा कि मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) अंतिम उपयोगकर्ताओं यानी ग्राहकों पर लागू नहीं होता है. वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर



से यूपीआई शुल्क को लेकर लगाए गए आरोपों को अफवाह बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है. सीतारमण ने कहा कि एमडीआर का संबंध व्यापारियों से है और इसे आम यूपीआई ग्राहकों से जोड़ना सही नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य यूपीआई से भुगतान करने वाले

उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना नहीं है. ऐसे में मोबाइल से दुकानदार को भुगतान करने, ऑनलाइन खरीदारी करने या किसी सेवा के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एमडीआर के नाम पर अलग से शुल्क देने की बात नहीं है. वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि प्रस्तावित संशोधन से यूपीआई लेनदेन को शुल्क-मुक्त रखने वाली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और भविष्य में डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लगाने का रास्ता खुल सकता है. जयराम रमेश ने सरकार के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि यूपीआई व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए एमडीआर की आवश्यकता हो सकती है.

के लिए बैंकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को लगातार निवेश करना पड़ता है. इसमें भुगतान का बुनियादी ढांचा तैयार करना, नई तकनीक विकसित करना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना शामिल हैं.

एसबीआई को पहली तिमाही में 21,121 करोड़ का रिकॉर्ड

मुंबई, 7 अगस्त भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 21,121 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया जो सालाना आधार पर 10.23 प्रतिशत का उछाल है.

तिमाही के दौरान ब्याज से प्राप्त बैंक की शुद्ध आय 14.88 प्रतिशत बढ़कर 46,992 करोड़ रुपये और परिचालन लाभ 9.77 फीसदी बढ़कर 33,529 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बैंक ने तिमाही के दौरान कुल 110 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया. उसके पास ग्राहकों की जमा राशि 60 लाख करोड़ रुपये और ग्राहकों को दिया गया कर्ज 50 लाख करोड़ रुपये से



अधिक रहा. ऋण उठाव 18.63 प्रतिशत और जमा 9.73 प्रतिशत बढ़ा. तिमाही के दौरान बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है.

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का अनुपात एक साल पहले की तुल 36 आधार अंक कम होकर 1.47 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए नौ

गर्मी उत्पादों के 40 विज्ञापनों में कमियां

मुंबई. एडवर्टाईजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने अप्रैल और जून के बीच गर्मियों के मौसम पर केंद्रित पर्सनल केयर, कूलिंग अप्लायंसेस, एयर प्यूरीफायर, सनस्क्रीन, बिजनेसबल्स और ट्रेवल से जुड़े उत्पादों सहित अलग-अलग कैटेगरी के 40 विज्ञापनों की जांच की जिनमें से 39 को आदर्श मानकों की दृष्टि से कमियां पायी गयीं और संस्था ने इनमें बदलाव की जरूरत पर बल दिया है. इनमें केवल एक विज्ञापन ही अपने दावों को सही साबित कर सका. एएससीआई के अनुसार उपरोक्त 39 में से 21 विज्ञापनों को बिना किसी आपत्ति के संशोधित किया गया या वापस ले लिया गया, जबकि 18 विज्ञापनों को एएससीआई की सीसीसी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया.

एलआईसी का मुनाफा 23% से बढ़कर 13,492 करोड़ पहुंचा

नई दिल्ली, 7 अगस्त भारतीय बीमा नियम (एलआईसी) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है. अप्रैल से जून के बीच कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 13,492 करोड़ पहुंच गया.

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में एलआईसी को 10,987 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था. मुनाफे में इस मजबूत बढ़ोतरी के पीछे कंपनी की कुल आय के साथ-साथ प्रीमियम कलेक्शन में दर्ज हुई वृद्धि को अहम वजह माना जा रहा है. एलआईसी की ओर से जारी नियामकीय जानकारी के मुताबिक, जून तिमाही में कंपनी

बार मिलने वाले प्रीमियम से एलआईसी की आय बढ़कर 9,217 करोड़ हो गई. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 7,525 करोड़ था. यानी नए कारोबार से मिलने वाले प्रीमियम में करीब 1,692 करोड़ की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा रिन्यूअल प्रीमियम यानी पहले से चल रही बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण से मिलने वाली आय में भी वृद्धि हुई. यह आय 59,885 करोड़ से बढ़कर 61,833 करोड़ पहुंच गई. इससे पता चलता है कि कंपनी के मौजूदा पॉलिसीधारकों से मिलने वाला प्रीमियम भी लगातार मजबूत बना हुआ है.

विदेशी मुद्रा भंडार 10.51 अरब डॉलर बढ़ा

मुंबई, 7 अगस्त देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 31 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई.

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इस सप्ताह भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.512 अरब डॉलर बढ़कर 692.866 अरब डॉलर पर पहुंच गया. इससे पहले पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में 1.759 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई थी और यह 682.354 अरब डॉलर रहा था. ताजा आंकड़ों से देश की बाहरी वित्तीय स्थिति में मजबूती का संकेत मिलता है. विदेशी मुद्रा भंडार में हुई इस बढ़ोतरी में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण

भूमिका रही. देश के कुल भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं और इनमें होने वाला बदलाव कुल विदेशी मुद्रा भंडार को सीधे प्रभावित करता है. सोने के भंडार, विशेष आहरण अधिकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का आरक्षित भंडार भी कुल विदेशी मुद्रा भंडार के प्रमुख घटक हैं. विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत स्तर भारत को वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौरान बाहरी दबावों से निपटने में मदद करता है. साथ ही, इससे आयात जरूरतों को पूरा करने और रुपये की स्थिरता बनाए रखने के लिए भी बेहतर वित्तीय आधार मिलता है.

एमएसएमई-स्टार्टअप सहयोग पर बनी सहमति



जयपुर, 7 अगस्त भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत जयपुर में आयोजित 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई.

बैठक में सदस्य देशों ने औद्योगिक विकास, नवाचार, हरित तकनीक, डिजिटल परिवर्तन और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. सम्मेलन का

जयपुर में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक खत्म

मुख्य उद्देश्य पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देना रहा. 'सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' विषय पर आयोजित बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि जयपुर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ

सदस्य देशों के बीच डिजिटल तकनीक और औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और लचीला बनाने पर भी चर्चा हुई. जयपुर में हुई बैठक को ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

आधुनिक औद्योगिक विकास का भी प्रतीक है.

गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार सेंसेक्स 456 अंक टूटा निफ्टी भी फिसला

नई दिल्ली, 7 अगस्त घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को दबाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए.

सेंसेक्स 455.59 अंक टूटकर 78,499.17 अंक पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी-50 सूचकांक भी 65.35 अंक की गिरावट के साथ 24,570.65 अंक पर आ गया. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन

बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. शुरुआती कारोबार में बाजार की चाल को लेकर निवेशकों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन कारोबार आगे बढ़ने के साथ बिकवाली हावी होती गई. खासकर प्रमुख शेयरों में दबाव बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आ गए.

एआई स्मार्टफोन का 100 करोड़ निवेश

सिक्वोरिटी रिसर्चर्स सिस्टम की जाँच कर और कमियाँ पहचानकर स्मार्टफोन को और सुरक्षित बनाने में करेंगे मदद भोपाल, 7 अगस्त भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक नई पहल करते हुए, एआई+ स्मार्टफोन ने प्रोजेक्ट ट्रस्ट लॉन्च किया है. इस पहल का उद्देश्य टेक कम्प्युनिटी के साथ मिलकर देश का सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन इकोसिस्टम तैयार करना है.

इसके लिए कंपनी अगले पाँच सालों तक हर साल 20 करोड़ रुपए यानि कुल 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस पहल के जरिए एक एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स और सिक्वोरिटी रिसर्चर्स को स्मार्टफोन की सिक्वोरिटी और



यूजर्स का भरोसा मजबूत करने के लिए साथ आने का मौका मिलेगा. इस पहल के तहत कंपनी स्वतंत्र सिक्वोरिटी रिसर्चर्स को अपने सिस्टम की जाँच करने, उसकी सिक्वोरिटी को परखने और ऐसी कमियों की पहचान करने के लिए आमंत्रित कर रही है, जिन्हें समय रहते ठीक किया जा

सके, ताकि उनका असर ग्राहकों तक पहुँचने से पहले ही रोका जा सके. प्रोजेक्ट ट्रस्ट+ इस सोच पर आधारित है कि सिक्वोरिटी कोई एक बार पूरा होने वाला काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. जैसे-जैसे डिजिटल दुनिया तेजी से जुड़ रही है, वैसे-वैसे सुरक्षित स्मार्टफोन बनाने के लिए मिलकर काम करना, पारदर्शिता बनाए रखना और टेक कम्प्युनिटी की भागीदारी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है. यह पहल सिर्फ पारंपरिक बग बाउंट प्रोग्राम तक सीमित नहीं है,

समाचार विशेष

नवजोत सिंह सिद्धू क्या राजनीति में लौटेंगे

चंडीगढ़, 7 अगस्त. पूर्व क्रिकेटर और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले कुछ समय से राजनीति से दूरी बनाई हुई है. पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या राजनीति में लौटेंगे.

हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे लेकर अबतक कोई संकेत नहीं दिया है. पिछले चुनावों में एक्टिव रहने वाले सिद्धू इन दिनों इन दिनों वो पंजाब में भी नहीं हैं. सिद्धू इन समय कहाँ और क्या कर रहे हैं? बता दें कि सिद्धू इन दिनों धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं. मई महीने में जब नवजोत सिंह सिद्धू वृंदावन पहुंचे थे तो उन्होंने खुद बताया था कि वो धार्मिक यात्रा पर है. इस दौरान उन्होंने राजनीतिक सवालों का कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया था. वहीं पिछले दिनों वो उत्तराखंड पहुंचे. वो इस साल



लागातार दूसरी बार मां सुरकंडा देवी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने तीन दिन तक मंदिर में पूजा-अर्चना की और घंटों ध्यान-साधना भी की. सिद्धू को मां सुरकंडा मंदिर इतना भाया कि वे इसी वर्ष दूसरी बार मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूरे तीन दिन तक पूजा-अर्चना की. शांति और सूखने के लिए उन्होंने मंदिर में घंटों ध्यान-साधना भी की.

नवजोत सिंह सिद्धू ने लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाई हुई. उन्होंने एक बार फिर से टीवी और कमेंट्री में वापसी कर ली है. वहीं उनकी पत्नी नवजोत कौर ने अपनी दिन तक पूजा-अर्चना की. शांति और सूखने के लिए उन्होंने मंदिर में घंटों ध्यान-साधना भी की.

बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आए थे सिद्धू

नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2004 में बीजेपी में शामिल ज्वाइन की थी. 15 जनवरी, 2017 को उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था. कांग्रेस में आने के बाद वह अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीते थे. जुलाई 2021 में कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया. सिद्धू 2022 में आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर के सामने हार गए थे. ऐसे में अगर नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में वापसी करते हैं तो वो कांग्रेस या बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे. अगर उनकी पत्नी पत्नी बनाती है तो वो सवाल है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी दोनों चुनाव लड़ें. हालांकि इसे लेकर अभी दोनों की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है.

कुर्मी बनाम यादव बनाने की कवायद शुरू

लखनऊ, 7 अगस्त. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से प्रदेश में कुर्मी बनाम यादव राजनीति की हवा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं.

प्रदेश में एनडीए की सहयोगी सुभासपा के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुर्मी बनाम यादव के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है. उनसे पूछा है कि प्रधान यदि कुर्मी की जगह यादव होते तो वह इस्तीफा मांगते या बचाव करते.

नोट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने के विरोध में युवाओं के आंदोलन



के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से प्रदेश की राजनीति में इसे कुर्मी बनाम यादव की तरफ मोड़ने की कवायदें चल रही हैं.

चूंकि इस आंदोलन में कांग्रेस और सपा भी युवाओं के

सपा प्रमुख को जातिवाद पर घेरने की कोशिश

इसी कड़ी में मंत्री राजभर ने बुधवार को 'एक्स' पर एक पोस्ट कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जातिवाद पर घेरने की कोशिश की है. राजभर ने लिखा है कि मित्र अखिलेश यादव, आपसे एक प्रश्न है. अगर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जाति 'कुर्मी' की जगह 'यादव' होती तो आपका रुख क्या होता? क्या आप इस्तीफा मांगते या उनका बचाव करते? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, मित्र. गौरतलब है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा कुर्मी समाज के बीच अपनी मजबूत पेट बनाने में सफल रही थी. जिसका लाभ भी उसे मिला था. सपा के सिंबल पर कुर्मी बिरादरी से सात सांसद चुने गए.

साथ खड़े थे, इसलिए सपा को कुर्मी विरोधी साबित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव तक इस मुद्दे को ले जाने

की कोशिश हो सकती है, ताकि प्रदेश का कुर्मी मतदाता विपक्ष खासकर सपा से दूर हो जाए. प्रदेश की राजनीति में यह दोनों जातियां अहम रोल अदा करती हैं.

विडम्बना भाजपा, सपा- बसपा और कांग्रेस किस पार्टी में हो होगा सिर फूटखल

टिकट नहीं, बगावत तय करेगी चुनाव!

लखनऊ, 7 अगस्त. उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव सिर्फ जनता के बीच नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसकी एक बड़ी लड़ाई राजनीतिक दलों के भीतर भी होती है. जैसे-जैसे चुनाव करीब आता है. टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ने लगती है.

कोई अपने पांच साल का काम गिनाता है. तो कोई संगठन में अपनी पकड़ दिखाता है. जब इन सबसे बात नहीं बनती तो कोई जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी हवाला देने में पीछे नहीं रहता. लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलता है. यहीं से शुरू होती है नाराजगी, गुटबाजी और कई बार खुली बगावत.

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हर सीट पर टिकट मांगने वालों की संख्या कई बार दर्जनों में पहुंच जाती है.

जिसके बाद बगावत की आग उठती है. यही वजह है कि टिकट वितरण किसी भी पार्टी के लिए सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा माना जाता है.

बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?

सबसे पहले बीजेपी की ही बात करते हैं. लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर मैदान में उतरेगी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि कितने मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका मिलेगा और कितने नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा. अगर बड़ी संख्या में टिकट बदले जाते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ सकती है. वहीं अगर अधिकांश पुराने चेहरों को दोहराया जाता है, तो एंटी-इनकंबेंसी का सवाल भी उठ सकता है. भाजपा के सामने संगठन और

2027 के चुनाव में भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस चारों दलों के सामने सिर्फ विपक्ष को हराने की चुनौती नहीं होगी. उन्हें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना होगा. जो पार्टी टिकट बांटने में सामाजिक संतुलन, स्थानीय समीकरण, संगठन और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल बना पाएगी, उसकी चुनावी स्थिति मजबूत हो सकती है.

यूपी की राजनीति में अवसर कहा जाता है कि चुनाव का आधा संघर्ष टिकट तय होने से पहले ही शुरू हो जाता है. इसलिए 2027 की लड़ाई में टिकट बंटवारा भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, जितना चुनाव प्रचार.

सरकार दोनों के बीच संतुलन बनाना भी अहम चुनौती होगी.

सबसे बड़ा सवाल- कौन संभालेगा अपनी पार्टी?

सबसे बड़ा सवाल- कौन संभालेगा अपनी पार्टी? 2027 के चुनाव में भाजपा, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस चारों दलों के सामने सिर्फ विपक्ष को हराने की चुनौती नहीं होगी. उन्हें अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी साथ लेकर चलना होगा. जो पार्टी टिकट बांटने में सामाजिक संतुलन, स्थानीय समीकरण, संगठन और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के बीच बेहतर तालमेल बना पाएगी, उसकी चुनावी स्थिति मजबूत हो सकती है.

यूपी की राजनीति में अवसर कहा जाता है कि चुनाव का आधा संघर्ष टिकट तय होने से पहले ही शुरू हो जाता है. इसलिए 2027 की लड़ाई में टिकट बंटवारा भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, जितना चुनाव प्रचार.

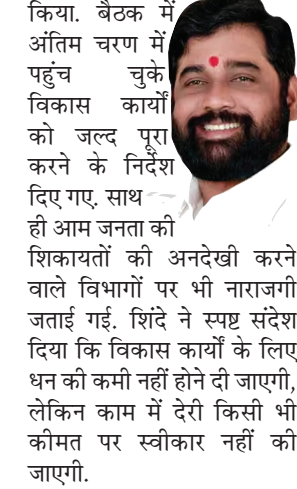
शिंदे गुट के 4 मंत्रियों की छुट्टी तय

महाराष्ट्र सरकार में होंगे बड़े फेरबदल, बैठक के बाद मचा हड़कंप

मुंबई, 7 अगस्त. महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जल्द ही बड़े राजनीतिक फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं. केंद्र सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब राज्य मंत्रिमंडल में भी भारी उलटफेर की चर्चा जोरों पर है.

इसी गहमागहमी के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपने कोटे के मंत्रियों और विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के कामकाज की करीब दो घंटे तक गहन समीक्षा करने को राजनीतिक गलियारों में बेहद अहम माना जा रहा है.

मंत्रालय में आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी विभागों के कामकाज की विस्तार से जायजा लिया. उन्होंने विकास कार्यों की स्थिति, लंबित परियोजनाओं, पर्याप्त बजट उपलब्ध होने के बावजूद काम में हो रही देरी तथा प्रशासनिक अड़चनों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों से जवाब-तलब



किया. बैठक में अंतिम चरण में पहुंच चुके विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए. साथ ही आम जनता की शिकायतों को अनदेखी करने वाले विभागों पर भी नाराजगी जताई गई. शिंदे ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन काम में देरी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी.

राजनीतिक सुओं के मुताबिक, बैठक के दौरान कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी असंतोष व्यक्त किया गया. चर्चा है कि दादा भुसे, संजय शिरसाट, संजय राठोड और स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर के प्रदर्शन पर शिंदे ने नाराजगी जताई है. हालांकि, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

नए चेहरों को मिल सकता है मौका

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र सरकार में भी फेरबदल किया जा सकता है. यूपी के अनुसार, अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन करने वाले कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है. हालांकि, महायुति सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बता दें कि पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कई बार दिल्ली का दौरा किया. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद से राज्य के सियासी गलियारों में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को चर्चाएं हो रही हैं.